सरकारों को विभिन्न शहरों और कस्बों में नौकरी करने वाली महिलाओं की होस्टल की आवश्यकता का मूल्यांकन करना चाहिए। सम्मेलन की सिफारिश को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रचालित किया गया था।

Accommodation to the Children's of Retiring Govt. Employees

3840. SHRI V. SREENIVASA PRASAD:
SHRI T. S. NEGI:
SHRI OSCAR FERNANDES:
SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:
SHRI CHANDRABHAN ATHARE PATIL:
DR. VASANT KUMAR PANDIT:
SHRI DAYA RAM SHAKYA:
SHRI RAM VILAS PASWAN:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1738 on the 23rd June, 1980 regarding Government accommodation to the children of the retiring Government employees and state:

(a) whether a final decision in this regard has since been taken;

(b) if so, what; and

(c) if not, what are the hurdles coming in the way of the Government in arriving at an early final decision in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The matter is under consideration and a final decision is expected to be taken shortly.

लखीमपुर खेरी जिले में सम्पूर्ण नगर में सहकारी चीनी मिल की स्थापना करना

3841. श्रीमती उषा वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर खेड़ी जिले में सम्पूर्णानगर में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना करने के लिये कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई महीने पूर्व भेजा गया था, राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की थी "लेकिन इस चीनी मिल की स्थापना के लिये अब तक अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस चीनी मिल की स्थापना के लिये एक लाइसेंस कब तक दिया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश की गई 1250 टन प्रतिदिन की पेराई क्षमता वाली सम्पूर्णानगर क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना के लिये लाइसेंस देने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) से (ग). जी, हां। लखीमपुर खेड़ी जिले में स्थित सम्पूर्णानगर में 1250 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता की सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभिस्तावित किया गया है। प्रस्तावित कारखाने को स्थापित करने की व्यवहार्यता के बारे में सरकार